WHISPERS IN THE CORRIDORS .COM
डॉ. सुरेश मेहरोत्रा
नईदुनिया से विशेष अनुबंध के तहत
राजनीतिक, प्रशासनिक व कॉर्पोरेट जगत की खबरें

राजनीतिक

• आरएसएस के जरिए GenZ युवाओं तक पहुंच!
जनरेशन के विरोध प्रदर्शनों और उनके प्रभावों के बाद, आरएसएस जल्द ही देशभर के जनरेशन युवाओं तक पहुंचने की योजना बना रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में इस अभियान की शुरुआत करेंगे।

• टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने अपनी लोकसभा सीट में बदलाव पर आपत्ति जताई
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सदन नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में अपनी बैठने की व्यवस्था में किए गए बदलाव पर आपत्ति जताई है और इस निर्णय का स्पष्टीकरण मांगा है।

• म्यांमार के साथ भूमि अदला-बदली? मणिपुर सीमा पर अनसुलझे विवाद अटकलों को हवा दे रहे
क्या नई दिल्ली संवेदनशील मणिपुर सीमा पर म्यांमार के साथ एक ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते की गुपचुप तैयारी कर रही है? विदेश मंत्रालय के हालिया बयानों ने गहन राजनयिक अटकलों को जन्म दिया है। संभावित क्षेत्रीय अदला-बदली की अफवाहों पर दबाव पड़ने पर, मंत्रालय ने स्वीकार किया कि 'सीमा पर कुछ क्षेत्रों का निपटारा अभी बाकी है' और पुष्टि की कि द्विपक्षीय वार्ता जारी है।
यह सुनियोजित रुख भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में हुए ऐतिहासिक भूमि अदला-बदली की कूटनीतिक भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मणिपुर में दशकों से सीमांकित न किए गए भूभाग और विवादित सीमा स्तंभों के कारण स्थानीय असंतोष और सुरक्षा संबंधी खतरे बने हुए हैं। भारत द्वारा सीमा बाड़बंदी और क्षेत्रीय अवसंरचना के विकास में तेजी लाने के साथ, इन लगातार बनी हुई मानचित्र संबंधी विसंगतियों का समाधान करना एक महत्वपूर्ण रणनीतिक प्राथमिकता बन गया है।
क्या रणनीतिक क्षेत्रीय आदान-प्रदान से कोई व्यावहारिक समाधान निकल सकता है? 2015 के समझौते ने सफलतापूर्वक राज्यविहीन क्षेत्रों को समाप्त किया, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया और भारत की पूर्वी सीमा को स्थिर किया। क्षेत्रीय अस्थिरता के बने रहने के कारण, नेप्यीडॉ के साथ इसी तरह का वार्तात्मक पुनर्गठन नई दिल्ली को अधिक नियंत्रण और स्थायी स्थिरता प्रदान कर सकता है।

• वीआईपी पर एक नया 'फरमान'
पूर्व सांसदों को अतिथि आवास की सुविधा नहीं मिलेगी। नए आदेश के अनुसार, यह सुविधा केवल वर्तमान सांसदों को ही मिलेगी, जिससे कई पूर्व सांसद असमंजस में पड़ गए हैं।

• कागजी कार्रवाई में बढ़ते विवादों से झारखंड की नौकरशाही पर दबाव बढ़ा
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) जैसे राज्य भर्ती निकायों में लगातार हो रहे परीक्षा लीक के आरोपों और व्यापक अनियमितताओं के चलते रांची भर में छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। हजारों नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सीबीआई द्वारा केंद्रीय जांच, अनियमित परीक्षाओं को रद्द करने और भर्ती व्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों की मांग कर रहे हैं। इस तीव्र जन आंदोलन ने राज्य के नौकरशाही तंत्र को कड़ी जांच के दायरे में ला दिया है। विपक्षी दलों से लेकर सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं तक, सभी राजनीतिक दलों के नेता वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, आयोग के अध्यक्षों और परीक्षा आयोजित करने वाले अधिकारियों को व्यवस्थागत विफलताओं के लिए जवाबदेह ठहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) से जांच का आदेश दिया, वहीं राजनीतिक विरोधियों ने राज्य प्रशासन पर उच्च पदस्थ नौकरशाहों को बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक नेताओं ने संस्थागत भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और सार्वजनिक भर्ती प्रबंधन में पारदर्शिता की पूर्ण कमी का आरोप लगाया है। छात्रों की शिकायतों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होने के साथ ही, नौकरशाही पर जनता का विश्वास बहाल करने का लगातार दबाव बढ़ रहा है। यह संकट झारखंड में प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर बढ़ते टकराव को उजागर करता है।

प्रशासनिक

• ओडिशाः राज्य के सबसे युवा कलेक्टर
मलकानगिरी के जिला कलेक्टर प्रथमेश अरविंद राजेशिरके ओडिशा राज्य के सबसे युवा जिला कलेक्टर हैं। 1996 में जन्मे राजेशिरके ओडिशा कैडर के 2021 बैच से संबंधित हैं।

• ईडी में प्रवर्तन निदेशक कौन होगा ?
प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निदेशक के पद के लिए विप्लव चौधरी का नाम भी चर्चा में है। वह एजीएमयूटी कैडर के 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

• केरल में डीजीपी पद के लिए होड़ जारी है।
एडीजीपी एमआर अजीत कुमार (1995) के निलंबन के बाद केरल के डीजीपी पद की दौड़ में नया मोड़ आ गया है। एडीजीपी एस. श्रीजीत (1996) पदोन्नति के प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं, जिनका नाम मुख्य सचिव ने अनुशंसित किया है। केरल के डीजी (अग्निशमन एवं बचाव) नितिन अग्रवाल 31 जुलाई, 2026 को सेवानिवृत्त हो गए, जिससे तत्काल रिक्ति उत्पन्न हो गई।

• सीबीआईसी में छह नए मुख्य आयुक्त
सीबीआईसी में अधिकारियों को मुख्य आयुक्त के पद पर पदोन्नति से संबंधित फाइल को इस महीने मंजूरी मिलने की संभावना है।

• क्या ज्ञानेश भारती अंडमान और निकोबार के नए मुख्य सचिव बनेंगे?
ज्ञानेश भारती को अंडमान और निकोबार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने की संभावना है। वे 1998 बैच के एजीयूएमटी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।

• बंसल को राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा से हटाया
राष्ट्रपति भवन सुरक्षा के संयुक्त पुलिस प्रमुख रहे वीनू बंसल का तबादला दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कर दिया गया है। वे 2004 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं।

• अभिषेक धनिया की आईटीबीपी के डीआईजी के रूप में नियुक्ति रद्द
अभिषेक धनिया को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इसके अलावा, आईपीएस अभिषेक धनिया (एजीएमयूटी: 2012) को 5 वर्षों की अवधि के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति और विदेशी कार्यभार/परामर्श सेवाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

• आईटीएस अधिकारी पेट्रोलियम मंत्रालय में कार्यभार संभालेंगे
मोहित कुमार अग्रवाल केंद्रीय कर्मचारी योजना (सीएसएस) के तहत प्रतिनियुक्ति के आधार पर चार साल की अवधि के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं।

• दिल्ली उच्च न्यायालय ने 138 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 अगस्त, 2026 से प्रभावी होने वाले 138 न्यायिक अधिकारियों के तबादलों का एक व्यापक आदेश जारी किया है।

मुख्यमंत्री करेंगे इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो-2026 का शुभारंभ

तीन दिवसीय इस आयोजन में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के साथ एक विशाल प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, लखनऊ : उत्तर प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका को और मजबूत करने जा रहा है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 से 13 अगस्त तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले तीसरे इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो में शामिल होने की सहमति प्रदान की है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा भी उपस्थित रहेंगे।
इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी एवं एमएम एक्टिव साइ-टेक कम्युनिकेशंस की ओर से उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के सह आयोजन में आयोजित यह तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य प्रदेश को बायोएनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, हरित उद्योगों और सतत औद्योगिक विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है।
इस आयोजन को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सहयोग प्राप्त है। 'कम-कार्बन विश्व के लिए उन्नत बायोएनर्जी समाधान' विषय पर आधारित यह आयोजन देश-विदेश के नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत, तकनीकी विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और निवेशकों को एक साझा मंच पर लाएगा।
स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से उभरते उत्तर प्रदेश के लिए आईबीईटी एक्सपो-2026 केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उद्योग साझेदारी और नीतिगत विमर्श का राष्ट्रीय मंच बनने जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य इस आयोजन के माध्यम से बायोएनर्जी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और नेट-जीरो लक्ष्यों की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश की भूमिका को और सशक्त बनाना है। इस अवसर पर आईएफजीई के महानिदेशक संजय गजू ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहभागिता उत्तर प्रदेश को बायोएनर्जी क्षेत्र के विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आईबीईटी एक्सपो-2026 नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत, नवाचारकर्ताओं और निवेशकों को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जहां नई साझेदारियों, निवेश के अवसरों और अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। हमें विश्वास है कि यह आयोजन भारत के बायोएनर्जी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली और निर्णायक मंच बनकर उभरेगा तथा देश की हरित अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। तीन दिवसीय इस आयोजन में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के साथ एक विशाल प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें कम्प्रेस्ड बायोगैस, एथेनॉल, बायोडीजल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, वेस्ट-टू-एनर्जी, बायो-मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, मरीन फ्यूल्स, बायोमास पेलेट एवं ब्रिकेट्स, कार्बन मार्केट, ग्रीन एट्रिब्यूट्स तथा अन्य उभरती बायोएनर्जी तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा।
इस सम्मेलन में विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नीति आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग तथा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी सहित विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भाग लेंगे।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, बागपतः श्रावण मास में चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर बागपत पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। बुधवार को मीडिया सेल जनपद बागपत की ओर से जारी एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
पुलिस के अनुसार मवीकलां कट बैरियर (थाना कोतवाली बागपत) सहित जनपद के विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग और डायवर्जन लागू किए गए हैं। कांवड़ यात्रियों को केवल निर्धारित कांवड़ मार्ग से ही गुजरने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही प्रमुख कट प्वाइंट्स और बैरियरों पर पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग और निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। अधिकारियों ने कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पुलिस द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करें। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने, अन्य यात्रियों का सम्मान करने और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

रजिस्ट्री से पहले जमीन के मालिकाना हक की होगी जांच

फर्जी दस्तावेजों के सहारे संपत्ति बेचने पर लगेगी रोक

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, लखनऊ : यूपी विधानसभा ने मंगलवार को स्टांप एवं पंजीयन विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। विधेयक के तहत रजिस्ट्री कार्यालय में संपत्ति के मालिकाना हक की भी जांच होगी। दूसरे विधेयक में दान की संपत्ति के निबंधन शुल्क को सर्किल रेट से जोड़ने का प्रावधान है। अब तक विभाग केवल संपत्ति के मूल्य, सर्किल रेट और राजस्व पहलुओं की जांच करता था।
संपत्ति के मालिक की पड़ताल खरीदार की जिम्मेदारी मानी जाती थी। इसी का फायदा उठाकर एक ही संपत्ति को कई लोगों को बेचने के मामले सामने आते थे। नए प्रावधानों से फर्जी दस्तावेज के सहारे संपत्ति बेचने पर रोक लगेगी।
विधेयक केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें केंद्रीय कानून में संशोधन का प्रावधान है। मंजूरी के बाद प्रदेश में इसके क्रियान्वयन के लिए शासनादेश जारी होगा। रजिस्ट्री के समय संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। रजिस्ट्री, खसरा-खतौनी, नामांतरण और हस्तांतरण अधिकार जैसे अभिलेखों की जांच की जाएगी। यदि दस्तावेज से विक्रेता का मालिकाना हक स्पष्ट नहीं होता है, तो उप निबंधक को रजिस्ट्री रोकने का अधिकार मिलेगा।

यूपी कैबिनेट का फैसलाः हर श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, ओवरटाइम पर दो गुना भुगतान करना होगा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, लखनऊ : उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता-2026 को मंजूरी दे दी। इसके लागू होने पर न्यूनतम मजदूरी का अधिकार अब केवल अनुसूचित नियोजनों तक सीमित न रहकर सभी पात्र श्रमिकों को मिलेगा। यानी किसी भी नियोजन या स्थान पर कार्यरत श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करते हुए चार श्रम संहिताएं अधिसूचित की हैं। नई संहिता इसी के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, वेतन भुगतान, समान पारिश्रमिक और बोनस से जुड़े चार केंद्रीय श्रम कानूनों का समावेश है। नई व्यवस्था में अनुसूचित नियोजन की व्यवस्था समाप्त कर मजदूरी का निर्धारण कौशल, कार्य की प्रकृति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भी लागू रहेगा। संहिता के अनुसार कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत मूल वेतन होगा, जिससे भविष्य निधि (पीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और ग्रेच्युटी जैसी सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ बढ़ेंगे। सेवा समाप्त होने पर श्रमिक का बकाया दो दिन के भीतर चुकाना अनिवार्य होगा। ओवरटाइम के लिए सामान्य दर से दोगुनी मजदूरी देनी होगी तथा वैधानिक कटौतियां कुल मजदूरी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। वेतन भुगतान से पहले वेतन पर्ची देना भी अनिवार्य किया गया है। संविदा श्रमिकों की मजदूरी और बोनस के भुगतान की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता पर होगी। वहीं, मृत कर्मचारी के बकाये का भुगतान नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाएगा। संहिता में नियोक्ताओं के लिए भी कई सुविधाएं दी गई हैं। नियोक्ताओं के अनुपालन भार को कम करते हुए तीन रजिस्टर और 10 प्रपत्रों की व्यवस्था, ऑनलाइन विवरणी तथा पहली बार उल्लंघन पर उपशमन का प्रावधान किया गया है। नो पर्सनल ऑफिस कांटेक्ट के सिद्धांत के तहत व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता कम करने पर जोर दिया गया है। विवादों में अब हाईकोर्ट के बजाय विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपील की जा सकेगी।
राज्य संपत्ति विभाग में सहायक लेखाकार के सभी पद अब भरे जा सकेंगे। पहले पदोन्नति वाले पदों को भरने में समस्या आती थी। विभाग में कुल 12 लेखाकार व सहायक लेखाकार के पद हैं। इनमें पहले तीन प्रवेश स्तर के और नौ पदोन्नति के थे। केवल प्रवेश स्तर के तीन पद ही भर पाते थे।
राज्य सरकार ने अब प्रवेश स्तर और पदोन्नति के पदों की संख्या एकसमान कर दी है। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 को मंजूरी मिली।

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, प्रयागराज : भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर आग की घटनाओं की रोकथाम तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए बहुस्तरीय अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहा है।
रेलवे ने सुरक्षा उपकरणों, प्रशिक्षित कर्मचारियों, आधुनिक तकनीक और त्वरित राहत प्रणाली के माध्यम से व्यापक इंतजाम किए हैं। यह जानकारी बुधवार को उमरे के जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने दी।
उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशनों पर पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र, रेत और पानी से भरी बाल्टियां, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, ऑटोमैटिक फायर अलार्म, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था, स्पष्ट निकास मार्ग तथा विद्युत प्रणालियों का नियमित सुरक्षा ऑडिट कराया जाता है। बड़े स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की स्कैनिंग भी की जाती है ताकि ज्वलनशील वस्तुएं लेकर यात्रा न करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। ट्रेनों में प्रत्येक कोच में कम से कम दो अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। पैंट्री कार और पावर कार में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, वाटर मिस्ट अग्निशामक यंत्र, आग एवं धुएं का पता लगाने वाली प्रणाली, अग्निरोधी सामग्री, इमरजेंसी विंडो तथा सुरक्षित विद्युत प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों के लिए इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट और आपातकालीन अलार्म बटन की भी व्यवस्था की गई है। रेलवे ने आपात स्थिति में त्वरित सहायता के लिए रेल मदद' हेल्पलाइन 139 को प्रभावी बनाया है, जिससे यात्री तुरंत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही स्टेशन प्रबंधक, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, टिकट निरीक्षक और अन्य फ्रंटलाइन कर्मचारियों को अग्निशमन, प्राथमिक उपचार और आपदा प्रबंधन का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है।
आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय रेलवे के पास देशभर में 177 दुर्घटना राहत ट्रेनें, 100 उच्च क्षमता वाली ब्रेकडाउन क्रेन और 170 दुर्घटना राहत चिकित्सा इकाइयां उपलब्ध हैं। आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन, दमकल विभाग, पुलिस, एनडीआरएफ और चिकित्सा संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जाता है।

मातृ वंदना योजना में उत्तर प्रदेश में लक्ष्य से अधिक हुआ पंजीकरण

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, लखनऊ : उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के प्रभावी क्रियान्वयन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में 31 जुलाई तक प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्य का 102.13 प्रतिशत हासिल कर देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने बताया कि सरकार ने तीन लाख 97 हजार 567 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया था, जबकि विभागीय अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के समन्वित प्रयासों से चार लाख छह हजार 058 महिलाओं का पंजीकरण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की मिशन मोड में कार्यशैली, मजबूत आंगनबाड़ी नेटवर्क और डिजिटल मॉनिटरिंग के कारण योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक तेजी से पहुंच रहा है। इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करने के साथ सरकारी योजनाओं की जमीनी पहुंच भी बढ़ी है।
योगी सरकार ने योजना को केवल औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित न रखकर इसे अभियान का स्वरूप दिया। गांव-गांव और वार्ड-वार्ड तक पहुंचकर पात्र महिलाओं की पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक नियमित समीक्षा बैठकों, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई ने पूरे अभियान को गति प्रदान की।

आपका राशिफल 06 अगस्त

मेष चू चे चो ला ली लू ले लो अ
कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। कल का परिश्रम आज लाभ देगा। यार दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। जोखिम से दूर रहना ही बुद्धिमानी होगी। आपकी योजना से लोग प्रभावित होंगे। शुभांक-3-5-7

वृष इ उ ए ओ वा वी वू वे वो
नवीन जिम्मेदारी बढ़ने के आसार रहेंगे। यात्रा शुभ रहेगी। अपने काम को प्राथमिकता से करें। कारोबारी काम में बाधा उभरने से मानसिक अशांति बनी रहेगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। यात्रा का दूरगामी परिणाम मिल जाएगा। कामकाज में आ रही बाधा को दूर करेंगे। शुभांक-2-5-7

मिथुन का की कु घ ङ छ के को हा
सुविधा और समन्वय बना रहने से कामकाज में प्रगति बन जाएगी। आर्थिक हित के काम को साधनों में मदद मिल जाएगी। यात्रा शुभ रहेगी। अपने काम पर पैनी नजर रखिए। विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य लाभ में समय और धन व्यय होगा। शुभांक-2-5-6

कर्क ही हू हे हो डा डी डू डे डो
समय पक्ष का बना रहेगा। कारोबारी काम में प्रगति बनती रहेगी। लेन-देन में आ रही बाधा दूर करने के प्रयास सफल होंगे। परिश्रम प्रयास से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। आलस्य का त्याग करें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। शुभांक-1-4-8

सिंह मा मी मू मे मो टा टी टू टे
यार-दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। जोखिम से दूर रहना ही बुद्धिमानी होगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी में सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होगा। शुभांक-2-6-8

कन्या टो पा पी पू ष ण ठ पे पो
शिक्षा में आशानुकूल कार्य होने में संदेह होगा। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। मित्रों से सावधानी रखें तो ज्यादा उत्तम है। शारीरिक सुख के लिए व्यसनों का त्याग करें। संतान पक्ष की समस्या समाप्त होगी। पठन-पाठन में स्थिति कमजोर रहेगी। शुभांक-3-5-8

तुला रा री रु रे रो ता ती तू ते
खान-पान में सावधानी रखें। कामकाज में आ रहा अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। मान-सम्मान में वृद्धि व अच्छे कार्य के लिए रास्ते बना लेंगे। अपने हित के काम सुबह-सवेरे ही निपटा लें। आगे से रुपए पैसों की सुविधा नहीं मिलेगी। कामकाज सीमित तौर पर ही बन पाएंगे। शुभांक-3-5-8

वृश्चिक तो ना नी नू ने नो या यी यू
समाज में मान-सम्मान मिलेगा। कई प्रकार के हर्ष उल्लास के बीच मांगलिक कार्य सम्पन्न होंगे। आमोद-प्रमोद का दिन होगा और व्यावसायिक प्रगति भी होगी। स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार होगा। ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होगी और सज्जनों का साथ भी रहेगा। शुभांक-1-3-5

धनु ये यो भा भी भू धा फा ढा भे
कुछ कार्य भी सिद्ध होंगे। व्यर्थ की भाग दौड़ से यदि बचा ही जाए तो अच्छा है। प्रियजनों से समागम का अवसर मिलेगा। अवरुद्ध कार्य संपन्न हो जाएंगे। महत्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें। संतान की उन्नति के योग हैं। सभा-गोष्ठियों में मान-सम्मान बढ़ेगा। शुभांक-5-7-9

मकर भो जा जी खी खू खे खो गा गी
आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। कोई प्रिय वस्तु अथवा नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। सभा-गोष्ठियों में मान-सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक आस्थाएं फलीभूत होंगी। अल्प-परिश्रम से ही लाभ होगा। कामकाज में आ रही अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। शुभांक-1-6-8

कुंभ गू गे गो सा सी सू से सो दा
सुख-आनंददायी समय है। लाभदायक कार्यों की चेष्टाएं प्रबल होंगी। सक्रियता से अल्प लाभ का हर्ष होगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए समय अच्छा रहेगा। सुखद समय की अनुभूतियां प्रबल होंगी। मनोविनोद बढ़ेगा। व्यावसायिक का अवसर उत्तम होगा। ज्ञानार्जन का वातावरण बनेगा। शुभांक-1-3-8

मीन दी दू थ झ ञ दे दो चा ची
शुभ कार्यों का लाभदायक परिणाम होगा। कामकाज की अधिकता रहेगी। लाभ भी होगा और पुराने मित्रों से समागम होगा। व्यवसायिक अभ्युदय भी होगा और प्रसन्नताएं भी बढ़ेंगी। कामकाज की व्यस्तता से सुख-आराम प्रभावित होगा। धर्म-कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी। सभा-गोष्ठियों में मान-सम्मान बढ़ेगा। शुभांक-5-7-9

निर्माण में लापरवाही, अधिशासी अभियंता समेत 13 इंजीनियरों का वेतन रुका

अयोध्या। चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण कार्यों में लापरवाही और गुणवत्ता में कमी मिलने पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने लोक निर्माण विभाग (निर्माण खंड-तीन) के अधिशासी अभियंता सहित 13 इंजीनियरों के अगस्त माह के वेतन पर तत्काल रोक लगा दी है। सभी अधिकारियों को सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता में कमी और अधिकारियों की प्रभावी निगरानी का अभाव सामने आने पर जिलाधिकारी ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्रवाई की जद में अधिशासी अभियंता सत्यपाल सिंह, सहायक अभियंता अखिल वर्मा, विपिन कुशवाहा व पूर्ण कुमार रस्तोगी तथा अवर अभियंता विनोद कुमार, सिद्धार्थ वर्मा, मनोज कुमार श्रीवास्तव, करुणेश कुमार सिंह, प्रवीण कुमार शर्मा, मनोज कुमार, अशोक कुमार यादव, विनोद कुमार विश्वकर्मा और स्वतंत्र कुमार बीहड़ शामिल हैं।

जनसहभागिता से ही नशा मुक्त भारत का संकल्प होगा साकार : मुविवि

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, प्रयागराज : उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में नशा मुक्त भारत अभियान पखवाड़ा के अंतर्गत बुधवार को मानविकी विद्याशाखा की ओर से 'नशा मुक्ति अभियान : जनसहभागिता एवं चुनौतियां' विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन सरस्वती परिसर स्थित लोकमान्य तिलक शास्त्रार्थ सभागार में किया गया। कार्यक्रम राज्यपाल सचिवालय के निर्देशानुसार तथा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत्यकाम के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ।
प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज को नशा मुक्त बनाने में जनसहभागिता की भूमिका को मजबूत करना था। प्रतिभागियों ने नशे के सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक तथा स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों पर प्रभावशाली विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी गंभीर बाधा बनता है। वक्ताओं ने युवाओं से नशे से दूर रहने तथा समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।
प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने युवाओं पर नशे के बढ़ते प्रभाव, पारिवारिक उत्तरदायित्व, शिक्षा की भूमिका तथा जनसहभागिता के माध्यम से नशा मुक्त भारत के निर्माण जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। कई प्रतिभागियों ने कहा कि नशे की समस्या का समाधान केवल कानून से नहीं, बल्कि व्यापक जनजागरण और सकारात्मक सामाजिक वातावरण से ही संभव है।
निर्णायक मंडल ने प्रतिभागियों का मूल्यांकन विषय की समझ, तार्किकता, अभिव्यक्ति कौशल और प्रभावशीलता के आधार पर किया तथा विद्यार्थियों को जागरूकता और उत्साह की सराहना की। कार्यक्रम का आयोजन मानविकी विद्याशाखा के समन्वयक प्रो. सत्यपाल तिवारी के निर्देशन में किया गया। संचालन डॉ. अतुल कुमार मिश्र ने किया, जबकि शोधार्थी प्रतिनिधि संजय सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।